(ग) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के आरंभ होने के समय मौजूदा सभी प्राथमिक स्कूलों को 31 मार्च, 1995 तक पठन-पाठन उपस्कर संस्वीकृत किए गए हैं। अतिरिक्त शिक्षकों के 98% पद संस्वीकृत किए गए है तथा 55% अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जिन प्राथमिक स्कूलों में नामांकन 100 से अधिक है, उनमें तीसरा शिक्षक प्रदान करने की योजना के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अब उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी पठन-पाठन सामग्री प्रदान की जाएगी। आठवीं योजना के दौरान विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत, 30% कवरेज की योजना है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अत्यधिक ऊंचे मूल्य

607. **श्री सोमपाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अत्यधिक ऊंचे मूल्य के बारे में दिनांक 8 जुलाई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकर इन पुस्तकों के ऐसे ऊंचे मूल्य के कारणों की जांच कराने का विचार रखती है;

(ग) क्या यह सच है कि परिषद में सस्ते मूल्य के कागजों के उपलब्ध होने के बावजूद परिषद के कतिपय अधिकारियों द्वारा बाजार से मंहगे कागजों की खरीद किया जाना इन पुस्तकों के अधिक मूल्य निर्धारित करने का कारण है;

(घ) यदि हां, तो परिषद् के अधिकारियों द्वारा ऐसा करने के क्या कारण हैं और इन अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) समाचार पत्र की रिपोर्ट में किया गया उल्लेख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कक्षा XII के लिए प्रकाशित भौतिकी खंड की पाठ्य पुस्तक के वर्तमान संस्करण के संदर्भ में है जिसमें पिछले संस्करण की अपेक्षा काफी ज्यादा पृष्ठ हैं और जो बेहतर किस्म के कागज पर मुद्रित हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चित्रों की अधिक स्पष्टता के साथ छपाई की जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार पाठ्य पुस्तक की कीमत न लाभ न हानि की अनुमोदित कीमत निर्धारण पद्धति के अनुसार निर्धारित की गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

608. **श्री जनार्दन यादव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा लाभ दर्शाये जाने के बावजूद इसकी वित्तीय स्थिति बदतर हालत में है;

(ख) यदि हां, तो इसकी इक्विटी पूंजी सुरक्षित पूंजी और अधिशेष के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है और वर्ष 1991-92 से कम्पनी का ऋण-स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में और विनिवेश करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कम्पनी की वित्तीय स्थिति के मर्चेन्टनर शेयरों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, नहीं।

(ख) "सेल" की साम्या पूंजी, सुरक्षित पूंजी व अधिशेष की वास्तविक स्थिति और वर्ष 1991-92 से इसकी ऋण स्थिति को नीचे दिया गया है:—

(करोड़ रु०)

वर्ष	साम्या पूंजी	सुरक्षित पूंजी और अधिशेष बट्टे खाते में डाले जाने वाला निवल विविध व्यय	कुल ऋण (उस पर प्राप्त/देय ब्याज को छोड़कर)
1991-92	3986	957	7212
1992-93	3986	12186	9521
1993-94	3986	1677	11271
1994-95	3986	2570	12136

(ग) जी हां।

(घ) चालू वर्ष के दौरान "सेल" में अपनी शेयरधारिता का सरकार द्वारा योजनागत विनिवेश कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जबकि शेयर मूल्य विभिन्न घटकों द्वारा नियंत्रित होते है जिसमें बाजार का दबाव भी शामिल है, शेयरों के आंके जाने वाले संभावित मूल्य की स्थिति बता पाना संभव नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

609. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 अप्रैल, 1994 का और 18 मार्च, 1994 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न 5084 और तारांकित प्रश्न 288 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चालू गैर-योजना व्यय को नियत करने के लिए गठित समिति को उस रिपोर्ट की जिसे 21 दिसंबर, 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था, क्या स्थिति है; और

(ख) यदि इस संबंध में कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं, तो सरकार 17 और 31 जनवरी, 21 फरवरी, 15 और 28 मार्च तथा 25 अप्रैल, 1994 को पहले ही अनुस्मारक भेजे जाने के अलावा, राज्य सरकार से तत्काल प्रतिक्रिया जानने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) एवं (ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के योजनेतर व्यय के मौजूदा स्तर के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 21 दिसंबर, 1993 को उत्तर प्रदेश सरकार को टिप्पणियों हेतु भेजी गई थी।

उ० प्र० सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-91 के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को संस्वीकृत योजनेतर अनुदान राशि प्रदान करना जारी रखेगी।